RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

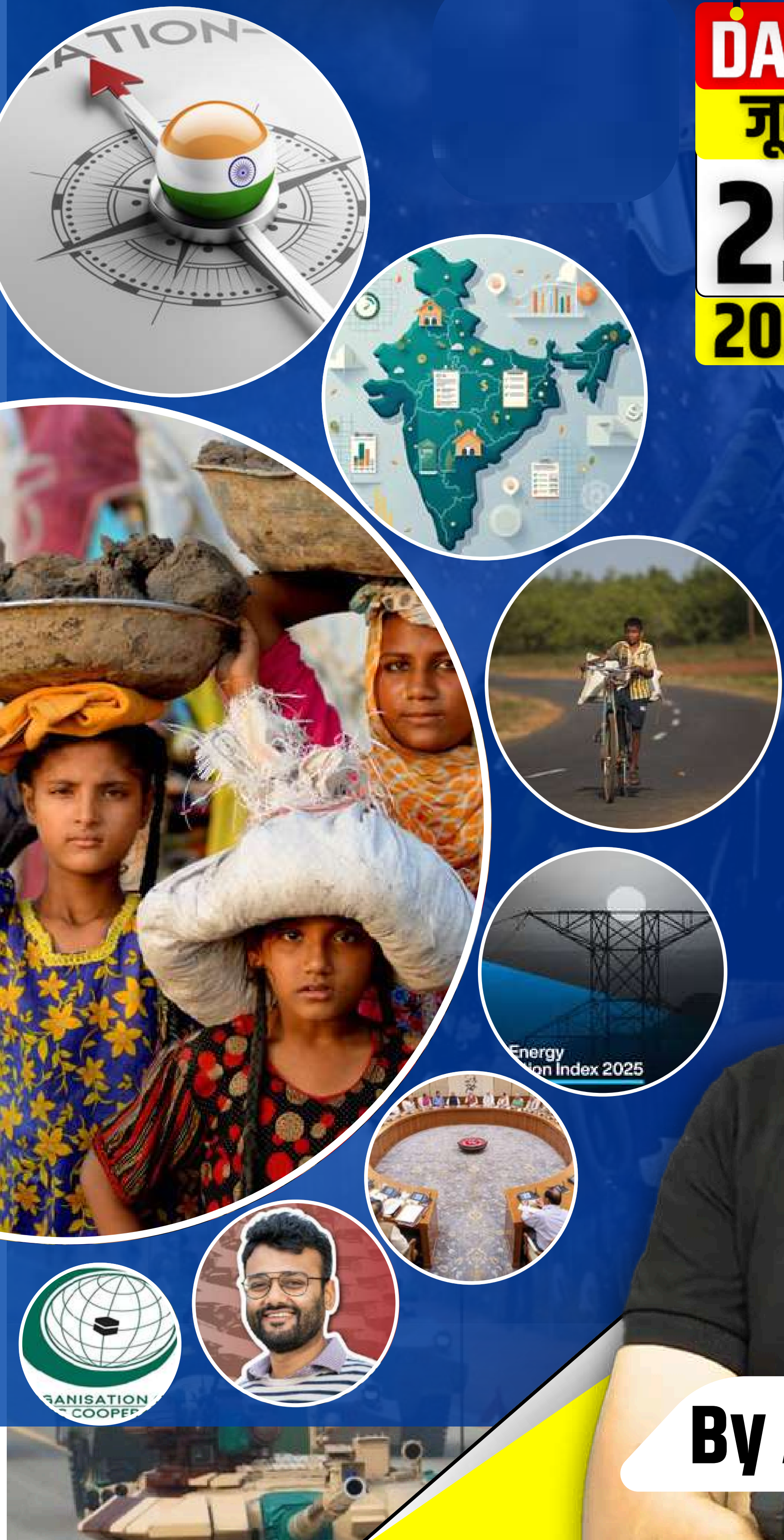

DATE
जून
25
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

मुद्रास्फीति और बेरोजगारी / Inflation and unemployment

संदर्भ:

मई माह में खुदरा **मुद्रास्फीति** की दर घटकर 2.8% पर आ गई, जो सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के भीतर है। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रभावी मौद्रिक नीति का परिणाम मानते हुए मीडिया में इसकी सराहना की जा रही है। किंतु इस उपलब्धि के साथ एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक संकेत की अनदेखी हुई है—**बेरोजगारी** दर में वृद्धि। नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, अप्रैल में 5.1% रही बेरोजगारी दर मई में बढ़कर 5.8% हो गई।

हालिया महंगाई में गिरावट का कारण क्या है जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है?

- **कृषि क्षेत्र की तेज़ वृद्धि ने मांग-आपूर्ति अंतर को घटाया:** वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर गैर-कृषि क्षेत्रों से अधिक रही। इससे खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ी और बाजार में संतुलन बना।
- **खाद्य मुद्रास्फीति में तेज़ गिरावट:** अक्टूबर 2024 में लगभग 11% पर थी खाद्य महंगाई, जो मई 2025 तक घटकर 1% से भी कम रह गई। यह गिरावट समग्र महंगाई दर को नीचे लाने में अहम रही।

मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध: फ़िलिप्स वक्र (Phillips Curve):

अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत – फ़िलिप्स वक्र – के अनुसार, अल्पकालिक अवधि में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक व्युत्क्रम (inverse) संबंध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि:

कम बेरोजगारी ➤ अधिक मुद्रास्फीति

- जब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में होती है और बेरोजगारी कम होती है, तो लोगों की आय और खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है।
- इससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, और कंपनियाँ कीमतें बढ़ा देती हैं।
- नतीजा: मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है।

अधिक बेरोजगारी ➤ कम मुद्रास्फीति

- जब अर्थव्यवस्था संकट में होती है और बेरोजगारी अधिक होती है, तो लोगों की आय और खर्च घट जाते हैं।
- इससे बाजार में मांग घटती है, कंपनियों को कीमतें घटानी पड़ती हैं या छूट देनी पड़ती है।
- नतीजा: मुद्रास्फीति कम हो जाती है या कभी-कभी डिफ्लेशन (मूल्य में गिरावट) भी हो सकता है।

आरबीआई की मुद्रास्फीति नियंत्रण रणनीति-

वर्तमान आर्थिक हालात में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मुद्रास्फीति नियंत्रण नीति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाएँ सामने आ रही हैं:

1. ब्याज दर और मुद्रास्फीति के रुझानों में असंतुलन

- आरबीआई का मुख्य उपकरण, रेपो रेट में वृद्धि, हालिया महंगाई गिरावट (विशेष रूप से खाद्य मुद्रास्फीति) से मेल नहीं खाता।
- इससे यह सवाल उठता है कि क्या मौद्रिक नीति वास्तव में महंगाई को प्रभावित कर रही है।

2. मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ स्थिर, लेकिन ऊँची बनी हुई हैं

- भले ही वास्तविक मुद्रास्फीति घट गई हो, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं की महंगाई को लेकर अपेक्षाएँ अभी भी ऊँचाई पर बनी हुई हैं।
- यह आरबीआई के उस सिद्धांत को कमजोर करता है जिसके अनुसार वह जनता की अपेक्षाओं को नियंत्रित कर महंगाई को स्थिर रख सकता है।

3. प्रतिक्रियाशील, नहीं कि अग्रसक्रिय नीति दृष्टिकोण

- आरबीआई की नीतियाँ अक्सर महंगाई में बदलाव के बाद आती हैं, न कि उसे पहले से नियंत्रित करने के लिए।
- इससे नीति को प्रतिक्रियाशील (reactive) माना जा रहा है, जबकि अपेक्षा एक प्रोएक्टिव और मार्गदर्शी भूमिका निभाने की थी।

आगे की राह:

वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, नीति निर्माताओं को केवल मुद्रास्फीति नियंत्रण तक सीमित न रहकर **रोज़गार सृजन और समावेशी विकास** की दिशा में भी सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है:

1. द्वैत उद्देश्य अपनाना आवश्यक-

- भारतीय रिज़र्व बैंक जैसे नीति-निर्माताओं को केवल मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारणपर ही नहीं, बल्कि **बेरोजगारी की स्थिति को भी ध्यान में रखकर** मौद्रिक नीति बनानी चाहिए।
- इससे नीतियाँ अधिक **संतुलित, समावेशी और वास्तविक अर्थव्यवस्था के अनुकूल** बन सकेंगी।

2. समावेशी विकास के लिए क्षेत्रवार निवेश को बढ़ावा देना

- **श्रम-प्रधान क्षेत्रों** जैसे विनिर्माण (manufacturing), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), और सेवाक्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- इसके साथ-साथ **कृषि क्षेत्र में समर्थन बनाए रखना आवश्यक** है, ताकि खाद्य आपूर्ति स्थिर रहे और मूल्य स्थिरता बनी

घरेलू आय सर्वेक्षण / Household Income Survey 2026

संदर्भ:

2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) देश में पहली बार **घरेलू आय सर्वेक्षण (Household Income Survey)** आयोजित करेगा। यह सर्वेक्षण भारत में घरेलू आय के स्तर और वितरण को मापने के उद्देश्य से किया जाएगा, जो नीति निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस प्रक्रिया को प्रभावी और वैज्ञानिक बनाने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह (Technical Expert Group - TEG) का गठन किया गया है, जो सर्वेक्षण की पद्धति, डेटा संग्रहण और अनुमान तकनीकों पर मंत्रालय को मार्गदर्शन देगा।

उद्देश्य और लक्ष्य:

भारत में आय वितरण और सामाजिक योजनाओं की प्रभावशीलता को बेहतर समझने के लिए, नीचे दिए गए प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

1. भारतीय परिवारों में आय वितरण के पैटर्न को समझना
2. प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रभाव का मूल्यांकन करना
3. कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लक्षित वितरण सुनिश्चित करना
4. आय आंकड़ों के संग्रहण में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप होना

क्या है यह सर्वेक्षण?

- यह एक **राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण** होगा जो **भारत में आय वितरण** पर विश्वसनीय और मजबूत डेटा तैयार करने पर केंद्रित है।
- यह पहली बार होगा जब केवल घरेलू आय पर इतना व्यापक और विशिष्ट सर्वेक्षण किया जाएगा।

संबंधित मंत्रालय और संस्थाएं:

- आँकड़ा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण (NSS)
- तकनीकी विशेषज्ञ समूह जिसकी अध्यक्षता डॉ. सुरजीत एस. भल्ला कर रहे हैं

घरेलू आय सर्वेक्षण - इतिहास:

- **1950**: NSS की स्थापना और बड़े पैमाने पर घरेलू सर्वेक्षण शुरू
- **1955–1970**: NSS के 9वें, 14वें, 19वें और 24वें राउंड में आय पर प्रयोगात्मक सर्वेक्षण, लेकिन **आय की अधरिपोर्टिंग (underreporting)** के कारण सीमित सफलता
- **1983–84**: एक और पायलट स्टडी, जो **स्केलेबल परिणाम नहीं दे पाई**
- **आय के अनुमान बार-बार खपत और बचत से कम निकले**, जिससे नीति निर्माता ऐसे पूर्ण सर्वेक्षण से बचते रहे

2026 सर्वेक्षण की विशेषताएँ:

- यह भारत का **पहला पूर्ण रूप से घरेलू आय वितरण पर केंद्रित राष्ट्रीय सर्वेक्षण** होगा
- **TEG के मार्गदर्शन में** वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाएगा
- **सैम्पलिंग डिज़ाइन, परिभाषाओं और आकलन पद्धति** पर स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी
- **डिजिटल उपकरणों** का उपयोग कर तकनीक के प्रभाव को भी दर्ज किया जाएगा
- यह MoSPI की हालिया **सांख्यिकीय नवाचारों** (जैसे: अनिगठित क्षेत्र, सेवाक्षेत्र, निजी पूंजीगत व्यय और पर्यटन डेटा) पर आधारित होगा

महत्त्व:

- **आय वितरण को समझने में मौलिक डेटा गैप** को भरेगा
- **कल्याणकारी नीतियों की योजना और समावेशी विकास के मूल्यांकन** में सहायक
- भारत की **सांख्यिकीय संरचना को वैश्विक मानकों के समकक्ष** लाने में मदद
- **सटीक आर्थिक योजना और लक्षित राजकोषीय हस्तक्षेपों** के लिए आधार तैयार करेगा

बाल श्रम / Child labour

संदर्भ:

बाल अधिकार क्षेत्र में कार्यरत एक नेटवर्क द्वारा जारी हालिया अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2024-25 में *तेलंगाना, बिहार और राजस्थान* भारत के वे तीन प्रमुख राज्य बनकर उभरे हैं जहाँ *बाल श्रम से जुड़े मामलों में सबसे अधिक बचाव अभियान* चलाए गए और *सबसे अधिक गिरफ्तारियाँ* दर्ज की गईं। यह रिपोर्ट बाल श्रम के विरुद्ध राज्यों की सक्रियता को दर्शाती है, साथ ही यह संकेत देती है कि इन क्षेत्रों में समस्या की व्यापकता अब भी एक गंभीर सामाजिक चुनौती बनी हुई है।

2024–25: बाल श्रम के खिलाफ भारत में बड़ी कार्रवाई:

साल 2024–25 में भारत ने बाल श्रम के खिलाफ प्रयासों में तेज़ी देखी, जिसमें देशभर से **53,000 से अधिक बच्चों** को मुक्त कराया गया।

मुख्य तथ्य:

- बाल अधिकारों पर काम करने वाले नेटवर्क **Just Rights for Children (JRC)** और **Centre for Legal Action and Behaviour Change (C-LAB)** की एक हालिया रिपोर्ट में **शोषण के व्यापक स्तर** और इसे समाप्त करने में आ रही **संस्थागत चुनौतियों** को उजागर किया गया है।

शीर्ष तीन राज्य (बाल श्रमिक बचाव में अग्रणी)-

1. **तेलंगाना- *11,063 बच्चे***
2. **बिहार-3974 *बच्चे***
3. **राजस्थान- 3847 *बच्चे***

- इन तीन राज्यों ने राष्ट्रीय स्तर पर हुई कुल कार्यवाही में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

रिपोर्ट में सामने आया: 90% बच्चे "सबसे खराब प्रकार के बाल श्रम" में लगे थे-

बाल अधिकार नेटवर्क Just Rights for Children (JRC) और C-LAB की रिपोर्ट के अनुसार, मुक्त कराए गए **लगभग 90% बच्चे** ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत थे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन 182 के तहत "सबसे खराब प्रकार के बाल श्रम" की श्रेणी में रखा गया है। भारत इस कन्वेंशन को पहले ही अनुसमर्थित (ratify) कर चुका है।

प्रमुख क्षेत्र जहां बच्चे कार्यरत पाए गए-

- स्पा और मसाज पार्लर
- ऑर्केस्ट्रा मंडलियां
- घरेलू श्रम
- अनौपचारिक मनोरंजन सेवाएं

गंभीर शोषण की घटनाएँ:

- कई मामलों में बच्चों को **यौन शोषण**, **अश्लीलता**, और **वेश्यावृत्ति** जैसी परिस्थितियों में धकेला गया।
- ये तथ्य दर्शाते हैं कि बाल श्रम केवल आर्थिक शोषण नहीं, बल्कि **मानवाधिकार हनन और संगठित अपराध** से भी जुड़ा हुआ है।

बाल श्रम के दुष्परिणाम:

1. स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:

- बच्चे **खतरनाक कार्य स्थितियों** में काम करते हैं, जहाँ उन्हें **शारीरिक व मानसिक शोषण**, अत्यधिक कार्य घंटे और असुरक्षित वातावरण झेलना पड़ता है।
- इसके परिणामस्वरूप उन्हें **चोट, बीमारियाँ** और दीर्घकालिक **विकास संबंधी समस्याओं** का सामना करना पड़ता है।

2. शिक्षा से वंचित होना:

- बाल श्रमिक अक्सर **स्कूल नहीं जा पाते**, जिससे वे **साक्षरता और बुनियादी शिक्षा** से वंचित रह जाते हैं।
- इससे उनके भविष्य के अवसर सीमित हो जाते हैं और **गरीबी का दुष्चक्र** बना रहता है।

3. विकास में बाधा:

- यह बच्चों के **सामान्य बचपन को बाधित** करता है – उन्हें खेलने, सामाजिक मेलजोल और भावनात्मक विकास के अवसर नहीं मिलते।

रिपोर्ट में सिफारिशें:

1. राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन मिशन (National Mission to End Child Labour) शुरू किया जाए।
2. प्रत्येक ज़िले में Child Labour Task Force का गठन हो।
3. Child Labour Rehabilitation Fund की स्थापना हो।
4. शिक्षा और पुनर्वास की सुनिश्चित व्यवस्था हो, ताकि बचाए गए बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
5. 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए, जिससे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति रुके।
6. Zero-tolerance policy अपनाई जाए – विशेषकर सरकारी खरीद प्रक्रिया में बाल श्रम पर सख़्त प्रतिबंध लगे।
7. खतरनाक उद्योगों की सूची में विस्तार हो।
8. राज्य-विशिष्ट child labour policies बनें।
9. SDG 8.7 (बाल श्रम समाप्त करने की समय-सीमा) को 2030 तक बढ़ाया जाए।
10. अपराधियों पर समयबद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक / Energy Transition Index 2025

संदर्भ:

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index - ETI) में भारत को 118 देशों में **71वां स्थान** प्राप्त हुआ है।

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025:

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी इस सूचकांक में 118 देशों का मूल्यांकन **ऊर्जा प्रणाली के स्थायित्व, समावेशन और सुरक्षा** के आधार पर किया गया है।

वैश्विक मुख्य बिंदु-

- **स्वीडन** (स्कोर: 77.5) ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसके बाद **फिनलैंड** और **डेनमार्क** क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- **चीन** 12वें और **अमेरिका** 17वें स्थान पर रहा।
- अधिकांश देशों ने अपने स्कोर में सुधार किया, लेकिन सिर्फ 28% देश ही तीनों ऊर्जा आयामों (सततता, समावेशन, और सुरक्षा) में समान रूप से प्रगति कर सके, जो असमान विकास को दर्शाता है।

प्रदूषण और निवेश:

- वर्ष 2024 में स्वच्छ ऊर्जा में $2 ट्रिलियन का निवेश हुआ, फिर भी वैश्विक उत्सर्जन बढ़कर 37.8 अरब टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया – जो अब तक का सबसे गर्म वर्ष था।
- ऊर्जा मांग में 2.2% की वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण AI, डेटा सेंटर्स, कूलिंग और विद्युतीकरण था।

भारत संबंधी मुख्य बिंदु:

- भारत की रैंक **2024 में 63वें स्थान से गिरकर 2025 में 71वें स्थान** पर आ गई (कुल 118 देशों में), भारत का कुल स्कोर **53.3** रहा।

जहाँ प्रगति हुई:

- ऊर्जा तीव्रता (Energy Intensity) और **मीथेन (CH_4) उत्सर्जन में कमी**।
- **अनुकूल ऊर्जा विनियमन**, और **स्वच्छ ऊर्जा निवेश** में वृद्धि।

जहाँ सुधार की आवश्यकता है:

- ग्रिड विश्वसनीयता (grid reliability)
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच
- आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को और कम करना
- इसके लिए अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, श्रमशक्ति विकास और वित्त पोषण में और निवेश आवश्यक है।

ऊर्जा संक्रमण सूचकांक-

लॉन्च किया गया: विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)

उद्देश्य: देशों को **जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण** में उनकी प्रगति के आधार पर रैंक करना।

सूचकांक की प्रमुख विशेषताएँ:

1. मूल्यांकन का आधार: ETI रिपोर्ट में 118 देशों की ऊर्जा प्रणालियों का मूल्यांकन निम्नलिखित दो स्तरों पर किया गया:

ऊर्जा प्रणाली प्रदर्शन के तीन आयाम:

- **ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security):** स्थिर और लचीली ऊर्जा आपूर्ति की उपस्थिति, विविध स्रोतों का विकास, और ग्रिड/बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता।
- **समानता (Equity):** सभी वर्गों—उपभोक्ता और उद्योग दोनों—के लिए ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना।
- **सततता (Sustainability):** पर्यावरणीय प्रभाव कम करने वाले ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे कि कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रणालियाँ।

संक्रमण तत्परता के पाँच कारक:

- राजनीतिक प्रतिबद्धता
- वित्त और निवेश
- नवाचार (Innovation)
- अवसंरचना (Infrastructure)
- शिक्षा एवं मानव पूंजी

2. डेटा और स्कोरिंग पद्धति-

- कुल **43 संकेतकों** के आधार पर स्कोर निर्धारित किया गया।
- विभिन्न स्रोतों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संकलित डेटा का उपयोग किया गया।
- स्कोरिंग पैमाना: **0 से 100** के बीच।

गोडेल पुरस्कार / Gödel Prize

संदर्भ:

भारतीय मूल के प्रोफेसर ईशान चट्टोपाध्याय और डेविड ज़करमैन को 2025 का गोडेल पुरस्कार (Gödel Prize) प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके वर्ष 2016 के शोध पत्र 'Explicit Two-Source Extractors and Resilient Functions' के लिए मिला है।

गोडेल पुरस्कार के बारे में-

गोडेल पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ **कुर्ट गोडेल** के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने **गणितीय तर्कशास्त्र (mathematical logic)** में महत्वपूर्ण योगदान दिए – विशेष रूप से **"P vs NP"** जैसे मूलभूत प्रश्नों पर।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. उद्देश्य: यह पुरस्कार सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान (Theoretical Computer Science) के क्षेत्र में प्रकाशित उत्कृष्ट शोध पत्रों (outstanding papers) को मान्यता देता है।

2. प्रायोजक संस्थाएँ

- **EATCS:** The European Association for Theoretical Computer Science
- **ACM SIGACT:** Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory of the Association for Computing Machinery

3. पुरस्कार राशि: विजेता को **$5000 (अमेरिकी डॉलर)** की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

4. पात्रता (Eligibility): नामांकित शोधकार्य **सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान** के क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए।

निष्कर्ष: गोडेल पुरस्कार **गंभीर अकादमिक अनुसंधान और नवाचार** को प्रोत्साहित करता है और सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान में वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वाले शोधकर्ताओं के कार्यों को सम्मानित करता है।

प्राक्कलन समिति / Estimates Committee

संदर्भ:

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में आयोजित संसद तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की विधायिकाओं की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन इस समिति की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था।

संसद की प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)-

गठन वर्ष: 1950 यह समिति संसद की तीन वित्तीय स्थायी समितियों में से एक है, जिसका उद्देश्य **वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता** सुनिश्चित करना है।

संगठनात्मक संरचना:

- **कुल सदस्य:** 30
- **चयन प्रक्रिया:** लोकसभा अपने सदस्यों में से हर वर्ष इनका चुनाव करती है।
- **अध्यक्ष:** लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है।
- **कार्यकाल:** एक वर्ष
- **नोट:** कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई सदस्य मंत्री बना दिया जाता है, तो वह स्वत: समिति की सदस्यता से हट जाता है।

समिति के कार्य:

1. व्यय में मितव्ययिता और प्रशासनिक सुधार के सुझाव देना: बजट अनुमानों की समीक्षा कर यह समिति प्रशासनिक दक्षता और मितव्ययिता को बढ़ावा देने हेतु संगठनात्मक सुधार और खर्च कटौती के सुझाव देती है।

2. वैकल्पिक नीतियों की अनुशंसा: प्रशासन की कार्यकुशलता और मितव्ययिता बढ़ाने हेतु विकल्पीय नीतियाँ सुझाती है।

3. व्यय का मूल्यांकन: यह जांचती है कि क्या संसद द्वारा स्वीकृत निधि नीति के अनुरूप और उचित रूप से उपयोग हो रही है।

4. बजट प्रस्तुति को बेहतर बनाने के सुझाव: संसद में अनुमान (estimates) **किस रूप में प्रस्तुत किए जाएं**, इस पर सिफारिश करती है।

नव्या (NAVYA) पहल'

संदर्भ:
महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के सहयोग से 'नव्या (NAVYA) पहल' की शुरुआत की है। यह पहल adolescent girls (किशोरियों) को कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की दिशा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

NAVYA योजना (Nurturing Aspirations through Vocational Training for Young Adolescent Girls)

उद्देश्य:
NAVYA एक **पायलट पहल** है, जिसका उद्देश्य **16–18 वर्ष की किशोरी लड़कियों** (जो कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं) को **गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण** देकर सशक्त बनाना है।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. कौशल, आत्मविश्वास और अवसर प्रदान करना:
- योजना का लक्ष्य है किशोरियों को **कौशल प्रशिक्षण**, **आत्मविश्वास**, और **आजीविका के अवसरों** से लैस करना, जिससे वे **विकसित भारत @2047** की परिकल्पना में योगदान दे सकें।
- यह एक **समावेशी और आत्मनिर्भर भारत** के निर्माण की दिशा में कदम है।

2. कार्यान्वयन का भौगोलिक विस्तार:
- योजना **19 राज्यों के 27 जिलों** में लागू की जा रही है।
- इनमें **आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts)** और **पूर्वोत्तर राज्यों** को विशेष रूप से शामिल किया गया है।

3. मौजूदा योजनाओं का समन्वय:
- NAVYA योजना **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** और **पीएम विश्वकर्मा योजना** जैसी मौजूदा योजनाओं का लाभ उठाकर प्रशिक्षण और अवसरों का विस्तार करेगी।

निष्कर्ष: NAVYA योजना किशोरियों के कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। यह पहल लैंगिक समानता, रोज़गार सृजन और समावेशी विकास की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास है।

इस्लामी सहयोग संगठन / OIC

संदर्भ:
भारत ने हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारत से संबंधित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। भारत ने इन टिप्पणियों को अनावश्यक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद पर OIC की चुप्पी की कड़ी निंदा की है, इसे वैश्विक आतंकवाद विरोधी सहमति की उपेक्षा करार दिया है।

इस्लामी सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation - OIC)

स्थापना वर्ष: 1969

प्रकृति: एक अंतर-सरकारी संगठन (Intergovernmental Organisation)

उद्देश्य:
- OIC स्वयं को **"इस्लामी दुनिया की सामूहिक आवाज़"** के रूप में प्रस्तुत करता है।
- इसका उद्देश्य है **मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और सुरक्षा** करना, साथ ही **अंतरराष्ट्रीय शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना।**

सदस्यता:
- कुल **57 सदस्य देश**, जो मुख्यत: **मुस्लिम बहुल राष्ट्र** हैं।
- **भारत सदस्य नहीं है**, जबकि भारत में **विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या** निवास करती है।

अन्य प्रमुख तथ्य:
- **मुख्यालय:** जेद्दा, सऊदी अरब
- **आधिकारिक भाषाएँ:** अरबी, अंग्रेज़ी और फ्रेंच

निष्कर्ष
OIC एक प्रमुख वैश्विक मंच है जो मुस्लिम बहुल देशों के बीच सामूहिक हितों, धार्मिक एकता, और वैश्विक मामलों में समन्वय का प्रयास करता है, लेकिन भारत का इससे बाहर रहना कूटनीतिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है।

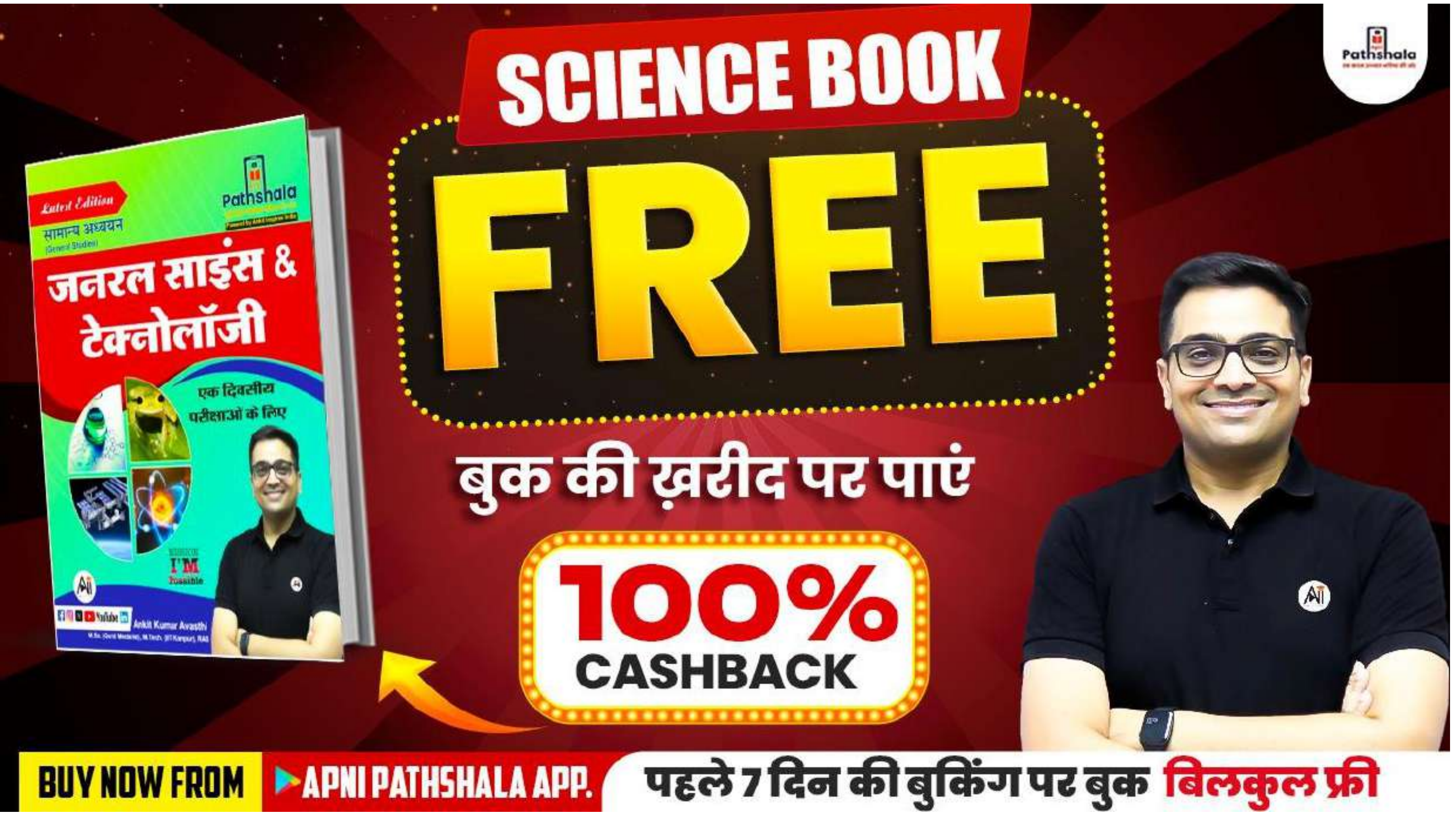
Pathshala
SCIENCE BOOK
FREE
Latest Edition
Pathshala
सामान्य अध्ययन
(General Studies)
जनरल साइंस &
टेक्नोलॉजी
एक दिवसीय
परीक्षाओं के लिए
Ankit Kumar Avasthi
बुक की ख़रीद पर पाएं
100%
CASHBACK
BUY NOW FROM
APNI PATHSHALA APP.
पहले 7 दिन की बुकिंग पर बुक बिलकुल फ्री

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
ECONOMY
POLITY
HISTORY
GEOGRPHY
1500X4
₹ 6000/-
₹4500/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

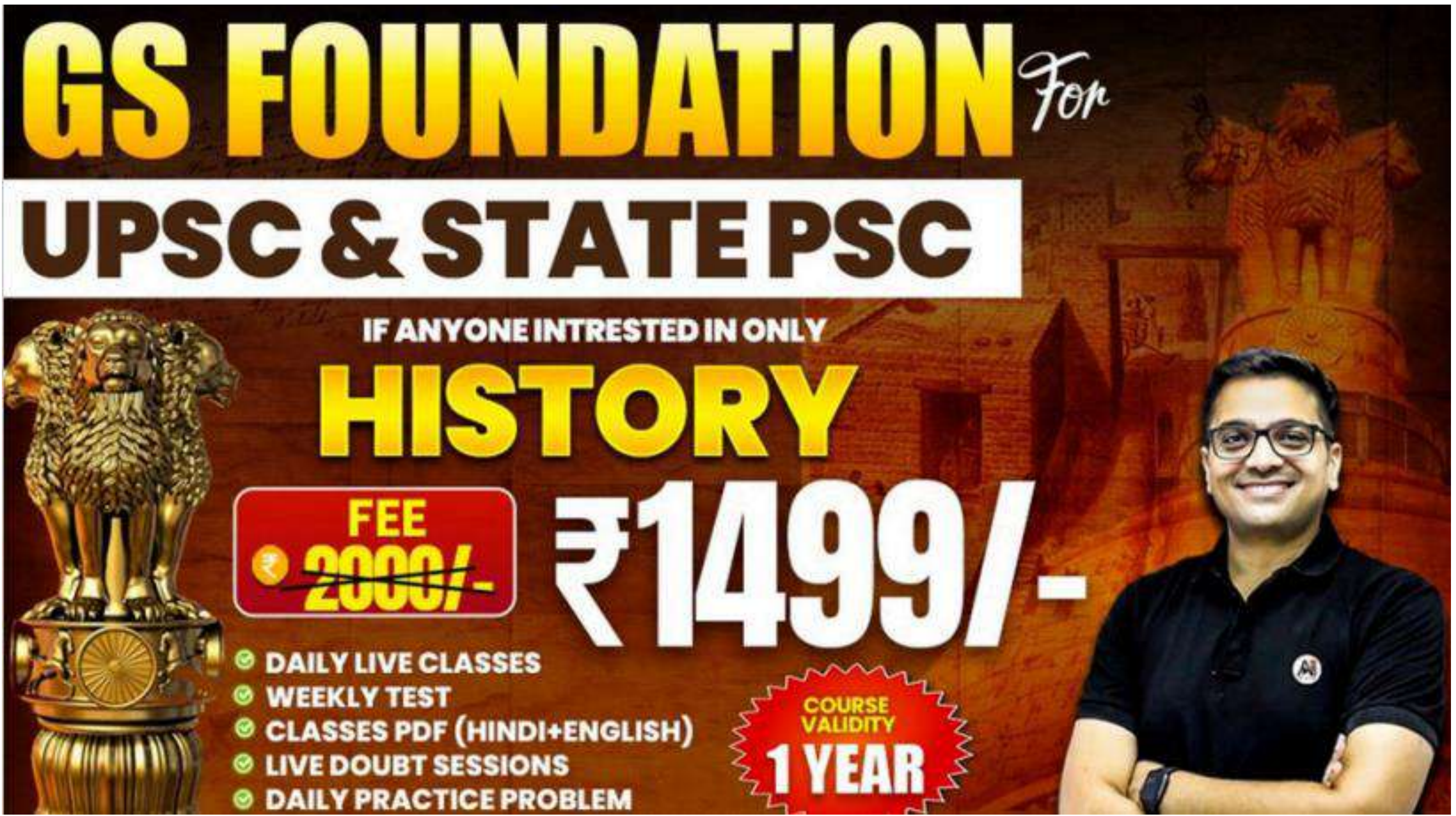
GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
HISTORY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
IF ANYONE INTRESTED IN ONLY
ECONOMY
FEE
₹ 2000/-
₹1499/-
DAILY LIVE CLASSES
WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTICE PROBLEM
COURSE VALIDITY
1 YEAR

जानिए
भारतीय संविधान
CONSTITUTION OF INDIA
मात्र
1499/-Year
Enroll Now !
1 year validity

GS FOUNDATION
Hand Written Notes
Pathshala
भारतीय भूगोल
भौतिक तथा विश्व भूगोल
BEST OFFER
1999Rs
4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Bilingual
By Ankit Avasthi Sir

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण
RNA : Real News Analysis
MONTHLY CURRENT AFFAIRS
MONTH
जनवरी, 2025
By Ankit Avasthi Sir
MONTHLY MAGAZINE
FREE!
अधिक जानकारी के लिए दिए गए
नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
Billingual
ANKIT AVASTHI SIR

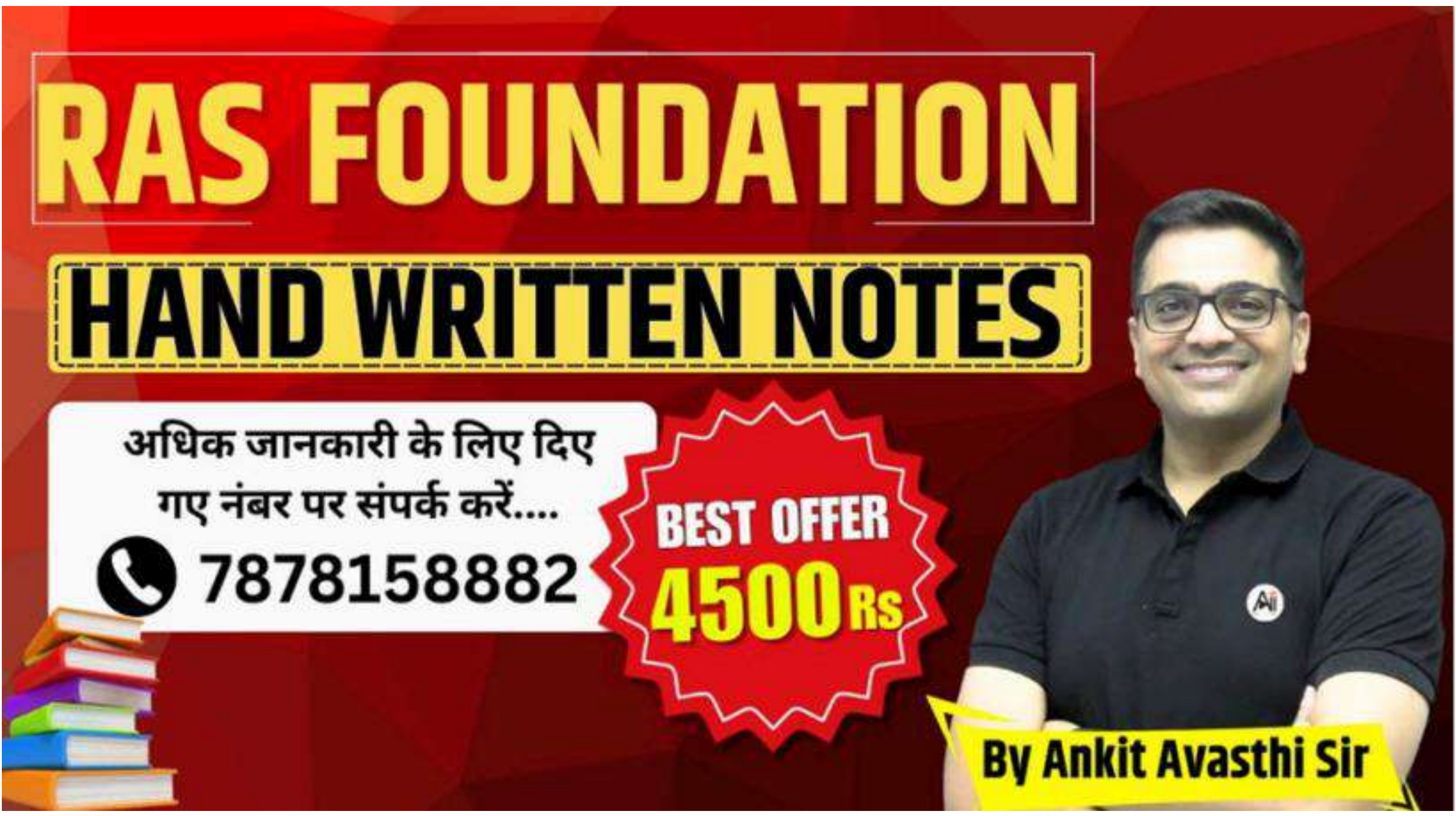
RAS FOUNDATION
HAND WRITTEN NOTES
अधिक जानकारी के लिए दिए
गए नंबर पर संपर्क करें....
7878158882
BEST OFFER
4500 Rs
By Ankit Avasthi Sir

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
BBK
COUPON CODE
ANKIT500
Course fee
₹1999/-
Course fee
₹1499/-
Special
OFFER ON
Father's
DAY
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुआत

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
COUPON CODE
ANKIT500
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
Course fee
₹1499/-
Special
OFFER ON
Father's
DAY
एक निवेश समझदारी से..
Course Validity
1 YEAR

CALL CENTRE

HOW MAY I HELP YOU

7878158882

AnkitInspiresIndia

Download "Apni Pathshsla" app now!

Follow us: